भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5339

25.03.2026 को उत्तर देने के लिए

एआई विश्वविद्यालय की स्थापना

†5339. श्री सौमेंदु अधिकारीः

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष के बजट में गैर-सरकारी क्षेत्र के "एआई और डीप-टेक" को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास पर विशेष ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित रूपरेखा या कार्यनीति के लिए वित्तीय वर्ष 2024 से आवंटित बजट और स्वीकृति का ब्यौरा क्या है और इस वर्ष के लिए कितना आवंटन किया गया है;

(ग) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल राज्य सहित देश में "एआई विश्वविद्यालय" स्थापित करने का विचार है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार निकट भविष्य में इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करेगी?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): सरकार ने वर्तमान बजट में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और गहन प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है।

इस दिशा में, सरकार ने 3 नवंबर 2025 को अनुसंधान, विकास और नवाचार (आरडीआई) योजना आरंभ की है, जिसके लिए छह वर्षों की अवधि हेतु कुल 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना का उद्देश्य रणनीतिक और उभरते क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) में निजी क्षेत्र के निवेश को प्रोत्साहित करना है, जिसमें क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक्स और अंतरिक्ष जैसी गहन प्रौद्योगिकियां; कृषि, स्वास्थ्य परिचर्या और शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और उसके अनुप्रयोग; ऊर्जा संक्रमण और जलवायु कार्रवाई; जैव प्रौद्योगिकी, जैव विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और चिकित्सा उपकरण; तथा डिजिटल कृषि सहित डिजिटल अर्थव्यवस्था शामिल हैं।

यह योजना अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ) के अंतर्गत स्थापित एक विशेष प्रयोजन कोष (एसपीएफ) के माध्यम से संचालित की जा रही है, जिसमें दो स्तरीय वित्तपोषण संरचना है। इस व्यवस्था के अंतर्गत, एसपीएफ कोष का संरक्षण करता है और द्वितीय स्तरीय कोष प्रबंधकों (एसएलएफएम) को धनराशि हस्तांतरित करता है। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड (टीडीबी) और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद (बीआईआरएसी) को एसएलएफएम के रूप में नामित किया गया है और उन्होंने फरवरी 2026 में प्रस्तावों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके अलावा, फंड ऑफ फंड्स सहित अन्य एसएलएफएम के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और उनका मूल्यांकन किया जा रहा है। यह योजना स्टार्टअप्स, कंपनियों और उद्योग-नेतृत्व वाले आरएंडडी संस्थाओं द्वारा प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर (टीआरएल) 4 और उससे ऊपर के प्रौद्योगिकी विकास को सहायता देती है।

इसके अतिरिक्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा राष्ट्रीय अंतर विषयक साइबर-भौतिकी प्रणाली मिशन (एनएम-आईसीपीएस) को लागू किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एआई, रोबोटिक्स, आईओटी, साइबर सुरक्षा और क्वांटम प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में 25 प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र (टीआईएच) स्थापित किए गए हैं। इस मिशन के अंतर्गत, भारत के लिए अनुकूलित बहु-माध्यमीय, बहुभाषी जनरेटिव एआई मॉडल विकसित करने हेतु भारत-जेन पहल को लागू किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान (एएनआरएफ), अपने उच्च-प्रभाव वाले क्षेत्रों में उन्नति मिशन (माहा) के अंतर्गत, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का समर्थन करता है, जिससे उद्योग-शिक्षा जगत के सहयोग को बढ़ावा मिलता है और एआई-संचालित समाधानों के विकास और व्यावसायीकरण में तेजी आती है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में एक मजबूत और समावेशी एआई परितंत्र बनाने के लिए पांच वर्षों में कुल 10,371.92 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मार्च 2024 में इंडियाएआई मिशन को मंजूरी दी। यह मिशन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य नवाचार को मजबूत करना, अनुसंधान और स्टार्टअप्स को सहायता देना, डेटा तक पहुंच बढ़ाना और एआई के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करना है। इंडियाएआई मिशन में सात प्रमुख स्तंभ हैं, जिनमें गणना क्षमता, मूलभूत मॉडल, डेटासेट प्लेटफॉर्म, एप्लिकेशन विकास, कौशल विकास, स्टार्टअप वित्तपोषण और सुरक्षित एवं विश्वसनीय एआई शामिल हैं।

इस मिशन के अंतर्गत, 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन करने वाले स्वदेशी बहुभाषी बहु-माध्यमीय बड़ा भाषा मॉडल भारतजेन जैसी पहलें आरंभ की गई हैं। इसके अलावा, सार्वजनिक सेवा वितरण और डिजिटल विश्वास को बढ़ाने के लिए स्वायत्त एलएलएम पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को मंजूरी दी गई है।

एनएम-आईसीपीएस, आरडीआई और इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत विस्तृत आवंटन (5 वर्षों के लिए) इस प्रकार है:

क्र. सं.	**वित्तीय वर्ष**	**बजट आवंटन (करोड़ रु.में)**
	एनएम-आईसीपीएस	
1	2024-25	815
2	2025-26	750.6
	आरडीआई योजना	
3	2025-26	20,000

घटक	**कुल व्यय (करोड़ रु. में)**
इंडियाएआई कंप्यूटिंग क्षमता	4563.36
इंडियाएआई फाउंडेशन मॉडल	1971.37
इंडियाएआई डेटासेट्स प्लेटफॉर्म	199.55
इंडियाएआई एप्लीकेशन विकास पहल	689.05
इंडियाएआई फ्यूचरस्किल्स	882.94
इंडियाएआई स्टार्टअप फाइनेंसिंग	1942.5
सुरक्षित और विश्वसनीय एआई	20.46
इंडियाएआई परिचालन लागत और आकस्मिक व्यय (1%)	102.69
कुल	10,371.92

(ग) से (घ): सरकार देश में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) और संबंधित संस्थागत तंत्रों की स्थापना के माध्यम से कई पहलें कर रही है।

इस संदर्भ में, स्वास्थ्य परिचर्या, कृषि और सतत शहरों जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) सहित प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के तीन उत्कृष्टता केंद्रों को मंजूरी दी गई है। इन उत्कृष्टता केंद्रों का उद्देश्य अनुसंधान-आधारित नवाचार को बढ़ावा

देना, बड़े पैमाने पर लागू करने योग्य एआई-आधारित समाधान विकसित करना और शिक्षा जगत, उद्योग और सरकार के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है।

इसके अतिरिक्त, इंडियाएआई मिशन के अंतर्गत, उच्च स्तरीय कंप्यूटिंग अवसंरचना को सुलभ बनाने, अनुसंधान और नवाचार को सहायता देने, और सार्वजनिक हित के लिए एआई एप्लीकेशन्ज़ के विकास को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

सरकार शिक्षा और कौशल विकास में एआई पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और शिक्षण ढांचों में एआई के एकीकरण जैसी पहल कर रही है, ताकि युवाओं को उद्योग-संगत कौशलों से लैस किया जा सके और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण किया जा सके। शिक्षा मंत्रालय उत्कृष्टता केंद्रों और उभरती प्रौद्योगिकियों में कौशल विकास कार्यक्रमों सहित ऐसी पहलों का समर्थन कर रहा है, जिससे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को लाभ मिल रहा है।

*****